

## उत्तराखंड उच्च न्यायालय

WPSS/393/2019 27 अक्टूबर, 2021 को

उत्तराखंड के उच्च न्यायालय में

नैनीताल में

अक्टूबर, 2021 के 27वें दिन

पहले:

माननीय श्री न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी

2019 की रिट याचिका (एस/एस) संख्या 393

बीच में:

दिनेश सिंह राणा. ....याचिकाकर्ता

(श्री पीयूष गर्ग, अधिवक्ता द्वारा)

और:

उत्तराखंड राज्य और अन्य। .....प्रतिवादी

(राज्य के स्थायी वकील श्री प्रदीप हैरिया द्वारा

उत्तराखंड के)

## निर्णय

याचिकाकर्ता ने पुलिस महानिरीक्षक, मुख्यालय, उत्तराखंड द्वारा पारित दिनांक 27.10.2018 के आदेश को चुनौती दी है, जिसके तहत उप-निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के उनके दावे को खारिज कर दिया गया है। आक्षेपित आदेश में बताया गया एकमात्र कारण यह है कि निंदा की सजा के खिलाफ याचिकाकर्ता की विभागीय अपील 24.10.2015 को पुलिस उप महानिरीक्षक, गढ़वाल रेंज द्वारा खारिज कर दी गई थी, जिसके परिणामस्वरूप, पदोन्नति प्रक्रिया में याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विचार नहीं किया गया था। पुलिस स्थापना समिति द्वारा नीचे.

2. आक्षेपित आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि याचिकाकर्ता ने लिखित परीक्षा और शारीरिक सहनशक्ति परीक्षण वाले पदोन्नति अभ्यास में भाग लिया और उसने 332 अंक (लिखित परीक्षा में 269 और सेवा रिकॉर्ड के लिए 63) प्राप्त किए। आक्षेपित आदेश में कहा गया है कि पदोन्नति के लिए याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी पर केवल उसकी विभागीय अपील पर निर्णय होने तक ही विचार किया गया था और उसकी अपील खारिज होने के बाद उसकी उम्मीदवारी खारिज कर दी गई थी।

3. याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन को खारिज करने के लिए पुलिस स्थापना समिति द्वारा जारी निर्देश, जिस पर भरोसा किया गया है, को आक्षेपित आदेश में पुनः प्रस्तुत किया गया है, जो उन मामलों में

सीलबंद कवर प्रक्रिया अपनाने का प्रावधान करता है जहां किसी पुलिस कर्मी के खिलाफ अनुशासनात्मक जांच या विभागीय अपील लंबित है।

4. यह एक तथ्य है कि इस न्यायालय की एक खंडपीठ ने 2018 के डब्ल्यूपीएसबी नंबर 19 में दिए गए दिनांक 07.09.2018 के फैसले के तहत निंदा की सजा के साथ-साथ अपीलीय प्राधिकरण (डीआईजी, गढ़वाल) द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.10.2015 को रद्द कर दिया है। श्रेणी।

5. चूंकि याचिकाकर्ता के पदोन्नति के दावे पर केवल 08.11.2013 को उसे दी गई निंदा की सजा के कारण विचार नहीं किया गया था, इसलिए, 2018 के डब्ल्यूपीएसबी नंबर 19 में दिए गए फैसले के मददेनजर, उत्तरदाताओं का कर्तव्य था कि वे उसके दावे पर विचार करें प्रमोशन के लिए. उक्त फैसले के बाद याचिकाकर्ता ने अपनी पदोन्नति के लिए अभ्यावेदन दिया, जिसे आक्षेपित आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया है।

6. इस न्यायालय की विनम्र राय में, लागू आदेश कानून की नजर में टिकाऊ नहीं है। याचिकाकर्ता पर लगाई गई निंदा की सजा उसकी विभागीय अपील को खारिज करने से अंतिम नहीं हुई, क्योंकि याचिकाकर्ता ने आगे बढ़कर इस अदालत के समक्ष इसे चुनौती दी और इस अदालत ने दिनांक 07.09.2018 के फैसले के जरिए इसे रद्द कर दिया। इस प्रकार, उत्तरदाता इस न्यायालय के फैसले के बाद पुलिस अधीक्षक, पौड़ी द्वारा दी गई निंदा की सजा पर भरोसा नहीं कर सकते। प्रतिवादी संख्या द्वारा लिया गया दृष्टिकोण। 3, यदि स्वीकार किया जाता है, तो 2018 के डब्ल्यूपीएसबी नंबर 19 में निर्णय सुनाया जाएगा।

7. अन्यथा भी, प्रतिवादी संख्या द्वारा लिया गया रुख। 3. दण्ड भोगने वाले अभ्यर्थी का परिणाम केवल उसकी विभागीय अपील के निस्तारण तक सीलबंद लिफाफे में रखा जाना स्वीकार नहीं किया जा सकता। किसी भी अन्य सरकारी कर्मचारी की तरह एक पुलिस कर्मी भी यूपी लोक सेवा न्यायाधिकरण अधिनियम, 1976 के तहत राहत का लाभ उठाने का हकदार है और उसके बाद वह सजा आदेश के खिलाफ न्यायिक उपाय की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। इस प्रकार, उसके परिणाम को उसकी दावा याचिका और रिट याचिका, जैसा भी मामला हो, पर निर्णय होने तक सीलबंद लिफाफे में रखा जाना चाहिए। इसलिए, याचिकाकर्ता की दावा याचिका और रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान उसके परिणाम को सीलबंद लिफाफे में रखने में उत्तरदाताओं की ओर से निष्क्रियता गलत थी।

8. कानून में यह स्थापित स्थिति है कि कोई भी अपनी गलती का लाभ नहीं उठा सकता है, इसलिए, उत्तरदाताओं को उनके द्वारा की गई गलती के लिए याचिकाकर्ता को पदोन्नति देने से इनकार करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इस प्रकार, इस न्यायालय को यह मानने में कोई झिझक नहीं है कि प्रतिवादी संख्या द्वारा याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन को अस्वीकार कर दिया गया है। 3 कानून की नजर में टिकाऊ नहीं है।

9. इस मामले को ध्यान में रखते हुए, रिट याचिका की अनुमति दी जाती है और प्रतिवादी संख्या 03 द्वारा दिनांक 27.10.2018 को पारित आदेश को रद्द किया जाये। प्रतिवादी नं. 3 को इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तारीख से छह सप्ताह के भीतर, कानून के अनुसार, पदोन्नति का दावा करने वाले याचिकाकर्ता के प्रतिनिधित्व पर फिर से विचार करने का निर्देश दिया जाता है।

(मनोज कुमार तिवारी, जे.) अर्पण